

प्रसावारण

EXTRAORDINARY

भाग **I**—खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160]

नई जिल्ली, सोमबार, प्रक्तूबर 11, 1971/प्रादियन 19, 1893

No. 160]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1971/ASVINA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पूज्य तंख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में एखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th October 1971

No. F. A.11013/E/134/71-Ad.IV.—Government introduced in respect of a number of excisable commodities, with effect from 1st June, 1968, the Self Removal Procedure under which excisable goods could be cleared on determination of the duty liability by the manufacturers themselves. This procedure has since been extended to all the excisable commodities with the exception of unmanufactured tobacco. The Finance Minister in the course of his Speech in the Lok Sabha on the 28th May, 1971, while presenting the Union Budget for 1971-72 had stated that he proposed to set up a Committee to review the Self Removal Procedure with a view to suggesting improvements which could reduce the leakage of revenue. The Government of India have accordingly, decided to appoint a Committee consisting of the following:—

Chairman

Shri B. Venkatappiah, formerly Member, Planning Commission and now Chairman, Rural Electrification Corporation Ltd.

Members

- (i) Shri Bhaskar Mitter, President, the Associated Chambers of Commerce and Industry of India.
- (ii) Shri G. B. Newalkar, President, Federation of Associations of Small Industries of India.
- (iii) Shri K. B. K. Rao, Senior Economist, National Council of Applied Economic Research, New Delhi.
- (iv) Shri S. P. Kampani, Member, Central Board of Excise & Customs, ex-officio Joint Secretary to the Government of India.

Shri Lachman Dev, an officer of the Indian Customs & Excise Service, will act as Secretary to the Committee.

- 2. The terms of Reference to the committee will be:
- (1) To review the working of the Self Removal Procedure Scheme in the Central Excise Department in all its aspects, including an analysis of its merits and demerits vis-a-vis the previous system of physical control and particularly enquire:
 - (a) to what extent the Self Removal Procedure has achieved the objectives set out when the Scheme was introduced.
 - (b) whether the Self Removal Procedure has led to, or afforded greater scope for, evasion of Central Excise duty and if so, to assess the magnitude of such evasion and also whether such evasion is confined to any particular industry/industries or any sector of the industry/ industries and the causes thereof; and
 - (c) to recommend changes considered necessary in existing Rules and/or procedure to plug the loopholes leading to evasion of duty.
- (2) To examine whether there are any items in the Central Excise Tariff (excluding tobacco) which, having regard to the safety of revenue, are not suited to be cleared under the Self Removal Procedure in its present form and if so, to suggest modifications or alterations in the mode of assessment and collection of duty on such items and suitable Rules and/or procedure therefor.
- (3) To examine the existing organisational and administrative set up of the Central Excise Department employed for levy and collection of Central Excise duties under the Self Removal Procedure, and to advise the Government in the light of the suggestions and recommendations made with reference to (1) and (2) above, on such reorganisation as may be considered necessary, keeping also in view the various agency functions (like those under the Customs, Gold Control and other Acts) which the Central Excise Department is at present entrusted with, and
- (3) To make any other recommendations germane to the objectives of this investigation.
- 3. The Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) before the 30th June, 1972.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

B. D. PANDE, Secy

वित्त मंत्रालय (राडस्य तथा बीमा विभाग)

संकल्प

मई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1971

सं∘ का० ए० विश्व 11013/ई/134/71-प्रज्ञा० IV.—उपादन शुल्क लगने योग्य बहुत सी वस्तुत्रों के सम्बन्ध में सरकार ने 1 जून 1968 से स्व-निर्धारण पर निकासी की कार्य विधि साग की जिसके प्रधीन स्वयं निर्माताओं द्वारा शुल्क की देनदारी निर्धारित करने पर उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तग्रों की निकासी की जा सकती है। इस कार्यविधि को ग्रव, ग्रांनिमित तम्बाकू को छोड़ कर, उत्पादन शुल्क लगने योग्य ग्रन्य सभी वस्तुग्रों पर लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने 28 मई, 1971 को लोक सभा में 1971-72 का केन्द्रीय बजट पेश करते ममय ग्रंपने भाषण के दौरान कहा था कि स्व-निर्धारण पर निकासी की कार्यविधि की समीक्षा करने के लिये वे एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं जो इस कार्यविधि में सुधार करने की दृष्टि से सुझाव दे जिससे कि राजस्व की हानि कम हो सके। एतदनुसार, भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। जिसका गठन इस प्रकार होगा:—

भ्रष्यक्षः श्री बी० बैंकटापैया योजना भायोग के भूतपूर्व सदस्य भौर ग्रामीण बैद्यतीकरण, निगम लिमिटेड के वर्तमान् भ्रष्ट्यक्षः;

- सदस्य
- (1) श्री भाष्कर मिस्तर, ग्रध्यक्ष, एसोसिटिड चेम्बर्स ग्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री भाफ इण्डिया।
- (2) श्री जी० वी० मैबलकर प्रध्यक्ष, फेडरेशन भाफ एसोसियेशन भाफ स्माल इण्डस्ट्रीज भाफ ६ण्डिया।
 - अो के० बी० के० राष,
 सीनियर इकानामिस्ट
 नेशनल काउन्सिल ग्राफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च, नई
 दिल्ली।
- (4) श्री एस० पी० कम्पानी, सदस्य, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड, पदेन सयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

भारतीय सीमागुस्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के एक भधिकारी, श्री लछमन न्देव, समिति, सिचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2. समिति के निवश-पद इस प्रकार होंगे:-

- (1) केन्द्रीय उत्पादन मुन्क विभाग में स्व-निर्धारण पर निकासी की कायविधि की उसके सभी पिछलोभों से समीक्षा करना जिसमें उसके गुण तथा दोषों का वास्तविक नियंत्रण की पिछली प्रणाली की तुलना में विष्नेषण करना भी ग्रामिल है और विशेष रूप औं इस बात की जांच करना कि:
 - (क) स्व-निर्धारण पर निकामी की कार्यविधि की योजना को लागू करते समय जो उद्देश्य निर्धारित किये गये थे उन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया गया है ;

- (ख) क्या स्व-निर्धारण पर निकासी कार्यविधि से केन्द्रीय उत्पादन गुल्क के अपवंचन को बढ़ावा मिला है श्रयवा उसके लिये ग्रधिक गुंजाइण पैंदा हुई है ग्रौर यदि एसा है तो इस प्रकार के अपवंचन के परिणाम को निर्धारित करना भ्रौर यह भी कि क्या इस प्रकार का भ्रपवंचन किसी खास उद्योग/उद्योगों श्रयवा उद्योग।उद्योगों के किसी क्षेत्र तक ही सीमित है ग्रौर उसके कारण क्या है; तथा
- (ग) वर्तमान नियमों तथा/म्रथवा कायविधियों में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करना जो भावश्यक समझे जायें जिससे उन किमयों को दूर किया जा सके जिनके क⊥रण शुल्क का भ्रापवंचन होता है।
- (2) इस बात की जांच करना कि क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में (तम्बाकू को छोड़कर) कोई ऐसी मदे हैं, जो राजस्व की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्व-निर्धारण पर निकासी की कार्यविधि के वर्तमान स्वरूप के ग्रधीन निकासी के उपयुक्त नहीं है और यदि ऐसा है तो ऐसी मदों पर शुल्क-निर्धारण और शुल्क वसूल करने के तरीके में संशोधन श्रथवा परिवर्तन करने श्रौर उसके लिए उपयुक्त नियम और/श्रथवा कार्याविधि का सुझाव देश।
- (3) रब-निर्धारण पर निकासी की कायविधि के प्रधीन केन्द्रीय उत्पादन णुल्क लगाने ग्रीर उन्हें वमृल करने के लिए नियोजित केन्द्रीय उत्पादन णुल्क विभाग के वतमान संगठनात्मक ग्रीर प्रणासन्तिक ढांचे की जांच करना ग्रीर उपयुक्त (1) ग्रीर (2) के संदर्भ में दिये गये सुझाव तथा सिफान्धों को ध्यान में रखते हुए ग्रीर साथ ही उन विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कायों (जैसे सीमाणुल्क, रवर्ण नियंवण ग्रीर ग्रन्थ ग्रिधिनयमों के ग्रिधीन विथे जाने वाले वाया) को ध्यान में रखते हुए जो इस समय केन्द्रीय उत्पादन ग्रुल्क विभाग को साँपें गये हैं, ऐसे पुनर्गटन के बारे में सरकार को मलाह देना जो ग्रावण्यक समक्षा जाय; ग्रीर
- (4) ऐसी कोई श्रन्य सिफारिणों करना जो इस जांच पड़ताल के उद्देश्यों ने संबंधित हो।
- 3. सिर्मात ने 30 जून, 1972 के पहले ग्रपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व ग्रीर बिमा विभाग) को पेश करेंगी।

मावेश

भ्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित भ्रधिकारियों/ विभागों को भेजी जाय श्रौर इसे सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाय।

बी० डो० पांडे, सचिव ।